

ब्यूज टुडे

भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से LNG का आयात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, 2024 के पहले 11 महीनों में अमेरिका से भारत में होने वाले LNG के आयात में साल-दर-साल 71% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के बारे में

- इसे प्राकृतिक गैस को -162°C (-260°F) तक ठंडा करके तरल अवस्था में परिवर्तित करके बनाया जाता है।
- चूंकि LNG मुख्य रूप से मीथेन (लगभग 90%) से बनी है, इसलिए यह गंधहीन, रंगहीन, गैर-विषाक्त और गैर-संक्षारक है।
- भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक है।

LNG पर भारत की निर्भरता क्यों बढ़ रही है?

- एनर्जी बास्केट में विविधता लाना: कोयले के उपयोग में कमी लाने के प्रयासों से ईंधन के तुलनात्मक रूप से स्वच्छ स्रोत LNG उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
 - सरकार का लक्ष्य 2030 तक एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाना है।
- गैस आधारित अर्थव्यवस्था: आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना।
- जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्य: LNG कोयले की तुलना में 40% और तेल की तुलना में 30% कम CO₂ उत्पन्न करता है। इससे यह जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ ईंधन बन जाता है।

LNG से जुड़ी चुनौतियां

- उच्च कीमत और अत्यधिक मूल्य अस्थिरता: जैसे- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में मांग-आपूर्ति संबंधी असंतुलन का पैदा होना।
- अपर्याप्त पाइपलाइन नेटवर्क: LNG को टर्मिनलों से उसके उपयोग वाले क्षेत्रों तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पाइपलाइन नेटवर्क अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। इससे पूरे देश में, खास तौर पर अलग-थलग क्षेत्रों में LNG के वितरण एवं उपलब्धता में बाधा आती है।
- सीमित भंडारण क्षमता: यह भारत को वैश्विक LNG बाजार में मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाता है।

LNG के लिए भारत की पहलें

- परिवहन और खनन क्षेत्रों में LNG के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए LNG नीति का मसौदा तैयार किया गया है।
- परिवहन क्षेत्रों में ईंधन के रूप में LNG को शामिल करने के लिए 2017 में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 को संशोधित किया गया था।

विविध क्षेत्रों में LNG की भूमिका

आवासीय उपयोग	बिजली उत्पादन	परिवहन	उद्योग
पानी और इमारतों को गर्म करने के साथ-साथ घरेलू में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाती है।	कोयले के कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकल्प के रूप में पॉवर प्लांट में बिजली के उत्पादन में उपयोग की जाती है।	भारी वाहनों और जहाजों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। इससे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है।	उर्वरकों, प्लास्टिक और वस्त्रों के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में कार्य करती है।

भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के 3 वर्ष पूरे हुए

इंडिया-UAE CEPA पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 मई 2022 को लागू हुआ था।

भारत-UAE CEPA के बारे में

- यह पिछले दशक में भारत द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला गहन और पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है।
- इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), निवेश आदि शामिल हैं।

भारत-UAE CEPA का महत्व

- इस समझौते से अगले पांच वर्षों के दौरान द्विपक्षीय वस्तु व्यापार के 100 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह सेवाओं में व्यापार के 15 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचने की अपेक्षा है।
- बेहतर व्यापार उदारीकरण और बाजार पहुंच के माध्यम से भारतीय कार्यबल के लिए दस लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- भारत के श्रम-प्रधान उत्पादों, जैसे- वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान आदि के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच को सक्षम बनाया जा सकेगा।
- संयुक्त अरब अमीरात से भारत को निर्यात किए जाने वाले लगभग 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क लागेगा। इससे पेट्रोरसायन, एल्यूमीनियम और तांबे के UAE कम्पोजिट निर्यातकों को लाभ होगा।
- यह समझौता ओमान, कतर जैसे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के साथ व्यापक व्यापार समझौतों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत-UAE CEPA के तहत हुई प्रगति

- द्विपक्षीय पण्य व्यापार: वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों देशों के बीच 43.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। यह वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग दोगुना होकर 83.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।
- निर्यात वृद्धि: वित्त वर्ष 2023-24 में गैर-तेल निर्यात 27.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। निर्यात मदों में मुख्य रूप से शामिल हैं- रिफाइनड कच्चा तेल, रत्न व आभूषण, उच्च तकनीक वाले सामान और रसायन आदि।
- MSMEs को बढ़ावा: दुबई में भारत मार्ट के साथ वैश्विक व्यापार में वृद्धि के साथ बाजार पहुंच और रोजगार में वृद्धि देखने को मिली है।

भारत-UAE द्विपक्षीय संबंध

- राजनयिक संबंध: देशों के बीच 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे।
- व्यापार: संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात 35.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है।
- रक्षा: दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास डेजर्ट ईंगल तथा संयुक्त सैन्य (थल सेना) अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जाता है।

नैसकॉम ने "भारत @2047: भारत को प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलना" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है, जो दर्शाती है कि भारत कैसे एक उच्च-आय वाले देश में परिवर्तित हो सकता है, और जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 23-35 ट्रिलियन डॉलर होगा।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- स्थिर GDP संवृद्धि: भारत को लगभग 8-10% की वार्षिक आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करनी होगी। निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था, विविध कौशल वाले कार्यबल का निर्माण जैसे कई पहलुओं पर जोर देना होगा।
- कुछ क्षेत्रों पर बल: सेवाएं और विनिर्माण क्षेत्रों को भारत की आर्थिक संवृद्धि को गति दे सकते हैं। ये क्षेत्र 10% की संवृद्धि दर प्राप्त कर रहे हैं, जबकि कृषि क्षेत्रों की संवृद्धि दर लगभग 6% होगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा: भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2023 की 24% से बढ़कर 2047 तक 70% हो जाएगी।

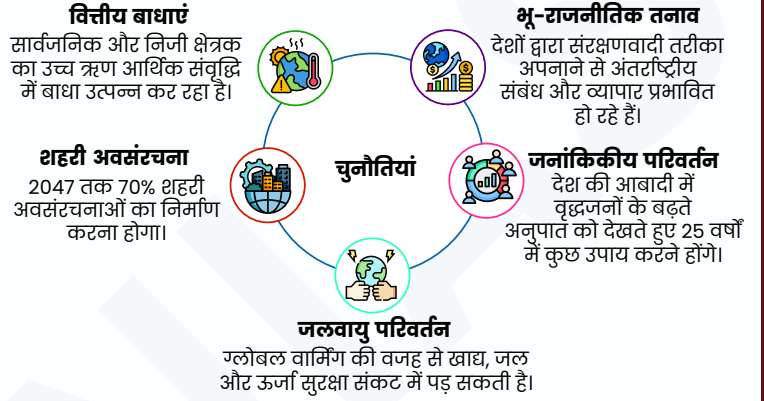
आर्थिक संवृद्धि को गति देने वाले क्षेत्र

- इलेक्ट्रॉनिक्स: निकट भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रोडक्ट सिमुलेशन और लंबी अवधि में क्लाउड कंप्यूटर व ब्रेन-इंस्पायर्ड न्यूरोमोर्फिक चिप के डिजाइन पर ध्यान देना होगा।
- ऊर्जा: मुख्य रूप से माइक्रोग्रिड, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) आदि में निवेश को बढ़ावा देना होगा।
- रसायन: AI-आधारित मॉलिक्यूलर डिजाइन और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित फॉर्मूलेशन पर ध्यान देना होगा।
 - उदाहरण के लिए- चीन ने विनिर्माण संसाधनों को एकीकृत करके उन्हें रासायनिक पार्कों में संगठित किया है।
- ऑटोमोटिव: विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहन और सालिड-स्टेट बैटरियों को अपनाने पर ध्यान देना होगा।
- सेवाएं: वित्त और बैंकिंग (ब्लॉकचेन आधारित लेन-देन); स्वास्थ्य-देखभाल (डिस्टेंस टेली-प्रेजेंट ट्रीटमेंट) जैसे क्षेत्रों पर जोर देना होगा।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- सरकार के लिए सिफारिशें:
 - निर्यात को बढ़ावा देने वाली अवसररचनाओं के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए,
 - आसियान, यूरोपीय संघ जैसे वैश्विक संगठनों के साथ भारत के हित वाले समझौते करने चाहिए।
- कॉर्पोरेट्स जगत के लिए सिफारिशें: नवीनतम तकनीक के साथ एकीकृत अवसररचना विकसित करने में निवेश बढ़ाना चाहिए।
 - उदाहरण के लिए- फेक्ट्री फ्लोर पर नवीनतम तकनीकी प्रणालियों को शामिल करना चाहिए, ताकि रियल टाइम आधारित डेटा प्राप्त किया जा सके।

आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने में चुनौतियां



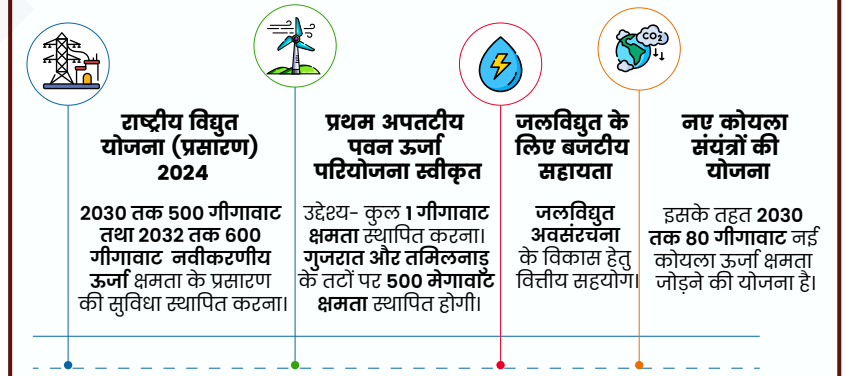
अंतराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने 'इलेक्ट्रिसिटी 2025' रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में बढ़ते विद्युतीकरण, विद्युत प्रणालियों के विस्तार और उत्पादन समिश्रण में मौसम पर निर्भर ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती हिस्सेदारी जैसे उभरते रुझानों पर चर्चा की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- वैश्विक
 - वैश्विक ऊर्जा मांग 2024 में 4.3% बढ़ी थी। इसके 2027 तक 4% के करीब बढ़ने का अनुमान है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए चीन विद्युत के सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरा है।
 - 2024 में विद्युत उत्पादन से वैश्विक CO₂ उत्सर्जन में 1% वृद्धि देखी गई थी, लेकिन 2025-2027 के बीच इसके स्थिर रहने की उम्मीद है।
 - 2025-2027 के दौरान विद्युत की बढ़ती मांग का 95% हिस्सा सौर, पवन और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा होने की संभावना है।
- भारत
 - भारत में 2024 में विद्युत की मांग में 5.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके 2025-2027 के दौरान औसतन 6.3% सालाना दर से बढ़ने की संभावना है।
 - भारत की कोयला-आधारित ताप विद्युत क्षमता 2032 तक 283 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है।
 - 2024 में कोयला 74% विद्युत उत्पादन के साथ भारत में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत बना रहा।
 - नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी 2024 की 21% से बढ़कर 2027 तक 27% तक पहुंचने की उम्मीद। इस हिस्सेदारी में सौर PVs प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
 - 2024 में परमाणु ऊर्जा में 13% की बढ़ोतरी देखी गई थी। 2031-32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.2 गीगावाट से तिगुनी होकर 22.5 गीगावाट हो जाएगी।

भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम



विद्युत की मांग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक

- वैश्विक: बढ़ता औद्योगिक उत्पादन (सौर पीवी सेल्स), एयर कंडीशनिंग (AC) का बढ़ता उपयोग, विशेष रूप से चीन में EV चार्जिंग अवसररचना और डेटा सेंटरों में विस्तार आदि।
- भारत:
 - 7% की उच्च आर्थिक संवृद्धि (IMF का अनुमान) और तीव्र गर्मी के परिणामस्वरूप भारत में AC की मांग बढ़ रही है।
 - पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं और बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2024 में संशोधन सौर संयंत्र स्थापना तथा बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहे हैं।

मर्सर-मेटल ने 'भारत का ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025' जारी किया

इस इंडेक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कार्यस्थलों के लिए भारतीय स्नातकों की रोजगार क्षमता का आकलन किया गया है।

इंडेक्स के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- ▶ भारतीय स्नातकों की समग्र रोजगार क्षमता: रोजगार क्षमता 2023 की 44.3% से घटकर 2024 में 42.6% रह गई थी। यह गिरावट विशेष रूप से मानव संसाधन, डिजिटल मार्केटिंग जैसी गैर-तकनीकी क्षमताओं की कमी के कारण दर्ज की गई है।
- ⊕ हालांकि, भारतीय स्नातकों ने AI जैसी तकनीकी क्षमता वाली नौकरियों में सबसे अधिक रोजगार-योग्य क्षमता प्रदर्शित की है।
- ▶ लैंगिक असमानता: 43.4% पुरुष स्नातक रोजगार योग्य हैं, जबकि महिला स्नातकों के लिए यह अनुपात 41.7% है।
- ▶ कॉलेज के आधार पर रोजगार क्षमता: टियर-1 कॉलेजों के स्नातकों की रोजगार प्राप्ति क्षमता सबसे अधिक है।
- ▶ सॉफ्ट स्किल्स में रोजगार-क्षमता: 50% भारतीय स्नातक भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional intelligence), रचनात्मकता जैसी सॉफ्ट स्किल्स में कुशल हैं।

भारतीय स्नातकों की कम रोजगार क्षमता के लिए जिम्मेदार कारक

- ▶ शिक्षा प्रणाली की खामियां: भारतीय कॉलेज विद्यार्थी व्यावहारिक कौशल विकास की तुलना में सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
- ▶ AI द्वारा नौकरियों में बदलाव: ऑटोमेशन नौकरी की भूमिकाओं को बदल रहा है। इससे निरंतर अपस्किलिंग की आवश्यकता बढ़ रही है।
- ⊕ 28% नियोक्ताओं का मानना है कि प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए 2025 तक उनके एक तिहाई कर्मचारियों के तकनीकी कौशल में महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता होगी।
- ▶ सॉफ्ट स्किल्स की कमी: शैक्षिक कार्यक्रमों में संचार, टीमवर्क और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी आवश्यक कार्यस्थल क्षमताएं शामिल नहीं की जाती हैं।

भारत में रोजगार क्षमता बढ़ाने से संबंधित पहलें

- ▶ कौशल विकास: प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना आदि चलाई जा रही हैं।
- ▶ महिलाओं की रोजगार-क्षमता: स्टैंड अप इंडिया, वुमन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग- किरण (WISE-KIRAN) जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

रोजगार क्षमता बढ़ाने में अलग-अलग हितधारकों की भूमिका

विद्यार्थी	कॉलेज	नियोक्ता
AI, कोडिंग, डेटा साइंस, टीमवर्क आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।	अधिक व्यावहारिक और उद्योग-की मांग आधारित शिक्षा पर जोर देना चाहिए।	रोजगार प्रशिक्षण और इंटरनशिप कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए, आदि।

प्रधान मंत्री ने भाषाई विविधता पर जोर देते हुए एक-दूसरे को प्रभावित करने और समृद्ध करने में भारतीय भाषाओं की भूमिका को रेखांकित किया

गौरतलब है कि भाषाई विविधता को निम्नलिखित दो प्रकार से समझा जा सकता है:

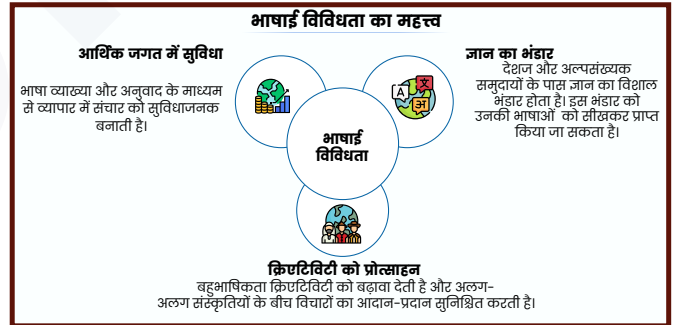
- ▶ देश में भाषाओं की कुल संख्या और
 - ▶ देश की आबादी में किसी एक भाषा को बोलने वालों का प्रतिशत।
- भारत में भाषाई विविधता
- ▶ स्थिति: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 99 से अधिक गैर-अनुसूचित भाषाएं, 22 अनुसूचित भाषाएं और 121 अन्य भाषाएं हैं।
 - ⊕ पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (2010) ने भारत में बोली जाने वाली 780 भाषाओं की पहचान की है। इनमें से 50 भाषाएं पिछले पांच दशकों में विलुप्त हो चुकी हैं।
 - ▶ भाषा परिवार: भारतीय भाषाएं मुख्य रूप से अग्रलिखित भाषा-परिवारों से संबंधित हैं- इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाई, तिब्बती-बर्मी आदि।

भारत में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक प्रावधान

- ▶ आठवीं अनुसूची: इसमें 22 अनुसूचित भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
- ▶ अनुच्छेद 29: यह अनुच्छेद नागरिकों के किसी भी वर्ग की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करता है।
- ▶ अनुच्छेद 350-B: इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

भारत में भाषाई विविधता बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम

- ▶ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: यह कम-से-कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा रखने का प्रावधान करती है।
- ▶ साहित्य अकादमी: यह संस्था पुरस्कार, प्रकाशन और अनुसंधान के माध्यम से भारतीय भाषाओं को समर्थन व संरक्षण प्रदान करती है।
- ▶ प्रौद्योगिकी संबंधी पहल: "भाषिणी" और अन्य AI-आधारित अनुवाद टूल; डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन जैसी पहलें आरंभ की गई हैं।
- ▶ शास्त्रीय भाषाएं: ऐतिहासिक महत्त्व और भाषाई योगदान के आधार पर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है।
- ▶ समिति: भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए 2021 में "भारतीय भाषा समिति" नामक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था।



अन्य सुर्खियां



फॉल्स किलर व्हेल

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तस्मानिया के एक सुदूर समुद्र तट पर फंस चुकी लगभग 90 फॉल्स किलर व्हेल को जीवित बचा लिया गया है।

फॉल्स किलर व्हेल के बारे में

- ▶ पर्यावास: यह प्रजाति विश्व में सभी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में तथा आम तौर पर गहरे अपतटीय जल में पाई जाती है।
- ▶ शारीरिक संरचना: यह गहरे भूरे रंग की होती है और अक्सर काले रंग की दिखाई देती है। हालांकि, इसके उदर (नीचे) पटल का एक छोटा सा हिस्सा हल्के रंग का होता है।
- ⊕ यह प्रजाति आकार में बड़ी और पतली होती है। नर मादाओं की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं।
- ▶ व्यवहार: यह प्रजाति मिलनसार होती है और मजबूत सामाजिक बंधन बनाती है।
- ⊕ अक्सर यह लघु उप-समूहों में पाई जाती है। इन उप-समूहों में एक या उससे अधिक फॉल्स किलर व्हेल होती हैं।
- ▶ मुख्य खतरे: पर्यावरण प्रदूषण, मानव द्वारा शिकार, शिकार के लिए फॉल्स किलर व्हेल के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा, आदि।



PM आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

प्रधान मंत्री ने PMAY-G के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया।

PMAY-G के बारे में

- ▶ मंत्रालय: 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा शुरू की गई थी।
- ▶ उद्देश्य: ग्रामीण गरीबों को मौलिक सुविधाओं के साथ सस्ते व पक्के मकान प्रदान करना। ग्रामीण भारत में "सभी के लिए आवास" सुनिश्चित करना।
- ▶ लक्ष्य: 4.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना। पहले मार्च 2022 तक 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना था। इसे बढ़ाकर 2024-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त मकान कर दिया गया।
- ▶ वित्तीय सहायता: इसके तहत पात्र लाभार्थियों को अपने स्थायी मकानों के निर्माण के लिए 3% रियायती ब्याज दर पर 70,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
- ▶ लाभार्थी: सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 और आवास+ (2018) सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए व्यक्ति। लाभार्थियों की ग्राम सभाओं द्वारा पुष्टि की जाती है।
- ▶ पात्रता मानदंड: बेघर परिवार तथा कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार।



कूनों राष्ट्रीय उद्यान

हाल ही में, कूनों राष्ट्रीय उद्यान में पाँच और चीतों को एनक्लोजर से खुले वन में स्वतंत्र छोड़ा गया।

कूनों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- स्थान: यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह विंध्य पहाड़ियों में विस्तृत है।
- इसका नाम कूनों नदी से लिया गया है। कूनों, चंबल नदी की सहायक नदी है।
- इसे 1981 में वन्यजीव अभयारण्य और 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था।
- यहां पाई जाने वाली वनस्पतियाँ उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन श्रेणी में आती हैं।
- वनस्पतियाँ: करधई, सलाई, खैर आदि।
- जीव-जंतु: चित्तीदार हिरण, सांभर, नीलगाय, बार्किंग डियर, आदि।



ग्रेट लेक्स

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से उत्तरी अमेरिका की ओंटारियो झील को खतरा है। यह झील 5 ग्रेट लेक्स में शामिल है।

ग्रेट लेक्स के बारे में

- 5 ग्रेट लेक्स निम्नलिखित हैं:
 - सुपीरियर (Superior): सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील।
 - मिशिगन (Michigan)
 - ह्यूरॉन (Huron): सबसे लंबी तटरेखा वाली झील।
 - ईरी (Erie): सबसे उथली (सबसे कम गहरी) झील।
 - ओंटारियो (Ontario): सबसे छोटी झील।
- ये 5 ग्रेट लेक्स सामूहिक रूप से पृथ्वी पर सबसे बड़ा फ्रेशवाटर सिस्टम है। इस सिस्टम में पृथ्वी का 1/5 सतही ताजा (मीठा) जल प्राप्त होता है।
- अवस्थिति: मिशिगन झील का संपूर्ण क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
 - अन्य चार झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं।
- अपवाह: लेक सुपीरियर का जल लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी और लेक ओंटारियो से होते हुए सेंट लॉरेंस नदी में मिलता है।



धर्म-गार्जियन

भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी जापान में आयोजित हो रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन' में भाग लेने के लिए रवाना हुई।

धर्म गार्जियन के बारे में

- यह भारत और जापान में बारी-बारी से आयोजित होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है।
- उद्देश्य: इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के मैडेट के तहत संयुक्त अर्बन वारफेयर और आतंकवाद-रोधी अभियान संचालित करते हुए दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है।



झूमोइर (झूमुर) नृत्य

भारत के प्रधान मंत्री असम के गुवाहाटी में झूमोइर बिनदिनी (मेगा झूमोइर) 2025 में उपस्थित होंगे। यह उत्सव असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

झूमोइर (झूमुर) नृत्य के बारे में

- यह एक लोक नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से असम की चाय उत्पादक जनजाति और आदिवासी समुदायों द्वारा फसल कटाई के मौसम में किया जाता है। यह नृत्य सामाजिक समावेशन, एकता और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है।
- इसमें महिलाएं मुख्य रूप से नृत्य और गायन में भाग लेती हैं, जबकि पुरुष मादल, ढोल, या ढाक (ड्रम), झांझ, बांसुरी और शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाते हैं।
- नृत्य में पहने जाने वाले परिधान समुदाय के अनुसार अलग-अलग होते हैं, लेकिन लाल और सफेद साड़ियाँ महिलाओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हैं।



क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियाँ (CIC)

हाल ही में, RBI ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (CICs) को क्रेडिट जानकारी प्रदान करने में विफल रहने की वजह से सिटीबैंक पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (CIC) के बारे में

- परिचय: यह ऋण, क्रेडिट कार्ड्स आदि के संबंध में व्यक्तियों एवं कंपनियों के पब्लिक डेटा, क्रेडिट लेन-देन और पेमेंट हिस्ट्री एकल करती है।
- महत्व: ऋण-दाताओं और क्रेडिट-दाताओं को मदद करने के लिए एक क्रेडिट स्कोर तैयार करती है। इसी आधार पर वित्तीय संस्थाएं ऋण के आवेदन को स्वीकार करती हैं या अस्वीकार करती हैं।
- लाइसेंसिंग और विनियमन: इन्हें RBI लाइसेंस देता है। इनका विनियमन क्रेडिट सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत किया जाता है।



बाथौवाद (Bathouism)

असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की सरकार ने बाथौवाद को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की।

बाथौ धर्म के बारे में

- बाथौ धर्म बोडो समुदाय का एक लोक-धर्म है। यह बथौबराई या सिबबराई की पूजा पर केंद्रित है। इसे बोडो जनजाति का सर्वोच्च देवता माना जाता है। यही कारण है कि इसे बाथौ धर्म कहा जाता है।
- बोडो भाषा में “बा” का अर्थ पाँच और “थौ” का अर्थ गहन दार्शनिक विचार होता है।
- ये पाँच तत्व हैं- बार (वायु), स (सूर्य), हा (पृथ्वी), ओर (अग्नि) तथा ओखरांग (आकाश)।
- बोडो जनजाति के बारे में
 - यह मैदानी भागों में रहने वाली असम की सबसे बड़ी देशज जनजाति है।
 - पारंपरिक रूप से इनका निवास क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे और भूतान की तलहटी में रहा है।
 - भाषा संबंध- असम-बर्मा समूह के तिब्बती-बर्मी भाषा परिवार से संबंधित हैं।

सुर्खियों में रहे स्थल



होंडुरास (राजधानी: टेगुसिगाल्पा)

भारत ने उष्णकटिबंधीय तूफान सारा से प्रभावित होंडुरास को मानवीय सहायता भेजी है।

होंडुरास के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति:
 - अवस्थिति: मध्य अमेरिका।
 - भूमि सीमाएं: इसके पश्चिम में ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर तथा दक्षिण एवं पूर्व में निकारागुआ स्थित है।
 - आसपास के समुद्र: इसके उत्तर में कैरेबियन सागर तथा दक्षिण में प्रशांत महासागर है।
- भौगोलिक विशेषताएं:
 - प्रमुख नदियाँ: पटुका और उलुआ।
 - सबसे ऊँची चोटी: माउंट लास मिनास।
 - खाड़ी: फोंसेका की खाड़ी। यह अल साल्वाडोर, होंडुरास और निकारागुआ से घिरी हुई है।

